रॉ शुगर सब्सिडी पर सहमति

▶ **नई दिल्ली...** केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार की अध्यक्षता में गठित मंत्रिसमूह की बैठक में चीनी मिलों को 40 लाख टन रॉ शुगर के निर्यात पर 3500 रुपये प्रति टन की दर से इंसेंटिव देने पर सहमति बन गई है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की आगामी बैठक में ही होगा।

(विस्तृत समाचार पेज 9 पर)

योजना ▶ दो वर्षों के दौरान 40 लाख टन रॉ शुगर निर्यात पर मिलों को इंसेंटिव

पवार के दबाव में रॉ शुगर निर्यात के लिए सब्सिडी बढ़ाने पर सहमति

बिजनेस भास्कर ▶ **नई दिल्ली...**

शुगर इकोनॉमी

3,500	2,000	1,400	800	1,450
रुपये प्रति टन सब्सिडी मिलेगी मिलों को	रुपये रॉ शुगर निर्यात सब्सिडी का प्रस्ताव था	करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा सरकार पर	करोड़ खर्च होते मूल प्रस्ताव मंजूर होने पर	करोड़ सब्सिडी दी थी 2007-08 में

आखिरकार चीनी मिलों को राहत पैकेज देने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार की ही चली। शरद पवार की अध्यक्षता में गठित एक मंत्रिसमूह (जीओएम) की शुक्रवार को हुई बैठक में चीनी मिलों को 40 लाख टन रॉ-शुगर के निर्यात पर 3,500 रुपये प्रति टन की दर से इंसेंटिव देने पर सहमति बन गई। हालांकि इस पर अंतिम फैसला आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की आगामी बैठक में ही होगा। इससे पहले यह मामला दो बार सीसीईए की बैठक में आ चुका है लेकिन कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री की सिफारिशों में अंतर होने के कारण इस पर फैसला नहीं हो पा पाया।

जीओएम की बैठक के बाद खाद्य एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री के वी थॉमस ने बताया कि चीनी मिलों को 40 लाख टन रॉ-शुगर के निर्यात पर 3,500 रुपये प्रति टन की दर से सब्सिडी देने पर सहमति बन गई है। इससे सरकार पर 1,400 करोड़ रुपये की सब्सिडी का भार पड़ेगा। केंद्र सरकार ने इससे पहले 19 दिसंबर 2013 को चीनी मिलों को 6,600 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण का पैकेज देने का फैसला किया था।

आर्थिक घाटे से जूझ रही चीनी मिलों को खाद्य मंत्रालय 2,000 रुपये प्रति टन की दर से सब्सिडी देने के पक्ष में था। चीनी मिलों को 800 रुपये प्रति टन की दर से इंसेंटिव देने पर सब्सिडी का भार 800 करोड़ रुपये का होता। उधर, इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) ने भी रॉ-शुगर के निर्यात पर 3,500 रुपये प्रति टन की दर से इंसेंटिव देने की खाद्य मंत्रालय से मांग की थी। चीनी मिलों को चालू पेराई सीजन 2013-14 के लिए 20 लाख टन और आगामी पेराई सीजन 2014-15 के लिए 20 लाख टन रॉ-शुगर के निर्यात पर इंसेंटिव दिया जायेगा तथा इंसेंटिव का भुगतान शुगर डेवलपमेंट फंड (एसडीएफ) से किया जायेगा।

केंद्र सरकार ने वर्ष 2007-08 में भी 60 लाख टन चीनी के निर्यात पर करीब 1,450 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी थी। इस्मा के अनुसार चालू पेराई सीजन 2013-14 में 250 लाख टन चीनी उत्पादन होने का अनुमान है। खाद्य मंत्रालय ने चालू पेराई सीजन में 241 लाख टन चीनी का उत्पादन होने का अनुमान लगाया है। देश में चीनी की सालाना खपत 230 से 235 लाख टन की होती है।

Business Bhaskar.
9-2-14